

मोदी के विकास के मॉडल पर हो रहा मप्र में क्रियान्वयन : डॉ. यादव

उद्योगपति समाज और सरकार दोनों के सहयोगी, सरकार उन्हें देगी पूरा प्रोत्साहन, उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए प्रदेश सरकार ने दी 5 हजार 260 करोड़ की सब्सिडी राशि

गोपाल (काप्र)

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि उद्योगपति समाज के लिए सरकारों और समाज के लिए सहयोगी हैं। वे लाखों परिवारों को रोटी, कपड़ा और मकान उपलब्ध कराते हैं। उद्योगपतियों के योगदान को सम्मान देने के लिए समाचार संस्थान ने इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड प्रदान कर सराहनीय कार्य किया है। अवार्ड सेरेमनी में डॉ. यादव का उद्योग जगत द्वारा सम्मान किया गया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में विकास के विक्रोंदीकृ मॉडल को अपनाते हुए विभिन्न क्षेत्रों में अच्छे परिवेश लाने के लिए बहत वातावरण निर्मित हुआ है। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में मध्यप्रदेश में उद्योगों के स्थाना और इनके माध्यम से बड़ी संख्या में व्यावायों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योगों से राष्ट्र



की प्रगति का कार्य हो रहा है। सरकारों का कार्य सिर्फ कानून व्यवस्था संभालना और बिजली, पानी की व्यवस्था करना नहीं, बल्कि जीवन मूल्यों के साथ विकास और परमार्थ के कार्यों को प्रोत्साहित करना है। प्रदेश की लगभग 9 करोड़ आबादी की बढ़ती के लिए राज्य सरकार प्रोत्साहन कर ही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्वहन कर ही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वीत साल हमें 5 हजार 260 करोड़ की उद्योग निवेश सब्सिडी राशि पूरी पारदर्शित के साथ

बीबीटी के जरिए निवेशकों के खातों में हस्तांतरित की। जीआईएस सिर्फ एक इवेंट नहीं था, बल्कि राज्य सरकार की प्रतिबद्धता का परिचयक आयोजन भी था।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का उद्योग हितेष्ठी नितियों को लागू करने उद्योग जगत की असंभवता के लिए राज्य सरकार की ओर से अधिनंदन किया गया। इस अवसर पर प्रमुख सचिव औद्योगिक विभाग रावेन्द्र कुमार सिंह और आयुक्त जनसम्पर्क डॉ. सुदाम खाड़े भी उपस्थित थे। कार्यक्रम में

सीओओ सुमित मोदी ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव का नेतृत्व ऐसा है जो असंभव कार्यों को संभव बनाता है। प्रदेश में इंज ऑफ इंडिंग बिजेनेस और व्यवस्थाओं में पारदर्शिता लागू कर उद्योगपतियों को आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश में सहयोगी बनाया गया है।

मुख्यमंत्री ने भारीत्य स्टेट बैंक के चीफ नियन्त्रक जेनरल चंद्रशेखर शर्मा को समानित करने के अलावा जिन उद्योगपतियों को इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड प्रदान किए उनमें

गेहूं उपार्जन के लिए किसान अब 9 तक करा सकते हैं पंजीयन: सरपूत

खाद्य, नारायिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि किसानों के हित में रखी विपणन वर्ष 2025-26 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिये पंजीयन की अवधि 9 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। पूर्व में पंजीयन की अवधि 31 मार्च 2025 तक नियन्त्रित की गई थी। श्री राजपूत ने किसानों से आप्रह किया है कि जिन किसानों ने अभी तक पंजीयन नहीं करवाया है, वे 9 अप्रैल तक गेहूं उपार्जन के लिये पंजीयन जरूर करायें। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रुपये है और राज्य सरकार द्वारा 175 रुपये प्रति किलो बानस दिया जा रहा है। इस तरह से गेहूं की खरीदी 2600 रुपये प्रति किलो बानस की दर से की जा रही है। उल्लेखनीय है कि गेहूं उपार्जन के लिये 31 मार्च तक 15 लाख 9 हजार 324 किसान पंजीयन करा चुके हैं। गेहूं का उपार्जन भी जारी है।

एवईजी के एजीक्यूटिव डायरेक्टर श्री मनीष गुलाटी, आपनेक्स के अनिल खेमसारा, दावत राइस के राजेंद्र, प्रियम सीमेंट के राजेंद्र संचेती, बालाजी पैकेजिंग ग्रुप के विकास मूंदडा, महाकौशल शुरा एंड पॉवर इंडस्ट्री के नवाब राजा, उदीप सोशल बेलफेर ग्रुप की सुमी पूरम श्रीती, गोयल चैंप के श्याम वैभव गोयल, आईसीसी इंफ्रा के दिलाप परवानी, ओटा इलेक्ट्रिकल सर्जिकल इक्सीपेंट के भूपेंद्र, संजय प्रसाद अग्रवाल, पुनीत खुराना, संदीप पाटीदार, सुरील लड्डा, विशाल अनिल जोशी, मनीष शाह शामिल हैं।

संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ अनिश्चितकालीन हड्डताल पर



गोपाल (काप्र)

लेन्किन 3 महीने के इंडताल के बाद भी कुकुट विकास निगम के प्रबंधन ने आदेश जारी नहीं किए। जिसके कारण कुकुट विकास निगम के संविदा कर्मचारी आज फिर से सड़कों पर उत्तर आए और कुकुट विकास निगम मुख्यालय के सामने हड्डताल पर उत्तर आदेश करावायी की।

गैरतलब है कि कुकुट विकास निगम में संविदा नीति लागू की जाने के लिए उद्योगपति ने कहा कि इसके बाद मध्य प्रदेश संविदा कर्मचारी आदेश के लिए राज्य सरकार के अध्यक्ष रामेश राठौर के नेतृत्व में उत्तर आदेश करावायी की।

गैरतलब है कि कुकुट विकास निगम में संविदा नीति लागू की जाने के लिए उद्योगपति ने कहा कि इसके बाद मध्य प्रदेश संविदा कर्मचारी आदेश के लिए राज्य सरकार के अध्यक्ष रामेश राठौर के नेतृत्व में उत्तर आदेश करावायी की।

गैरतलब है कि कुकुट विकास निगम में संविदा नीति लागू की जाने के लिए उद्योगपति ने कहा कि इसके बाद मध्य प्रदेश संविदा कर्मचारी आदेश के लिए राज्य सरकार के अध्यक्ष रामेश राठौर के नेतृत्व में उत्तर आदेश करावायी की।

गैरतलब है कि कुकुट विकास निगम में संविदा नीति लागू की जाने के लिए उद्योगपति ने कहा कि इसके बाद मध्य प्रदेश संविदा कर्मचारी आदेश के लिए राज्य सरकार के अध्यक्ष रामेश राठौर के नेतृत्व में उत्तर आदेश करावायी की।

गैरतलब है कि कुकुट विकास निगम में संविदा नीति लागू की जाने के लिए उद्योगपति ने कहा कि इसके बाद मध्य प्रदेश संविदा कर्मचारी आदेश के लिए राज्य सरकार के अध्यक्ष रामेश राठौर के नेतृत्व में उत्तर आदेश करावायी की।

गैरतलब है कि कुकुट विकास निगम में संविदा नीति लागू की जाने के लिए उद्योगपति ने कहा कि इसके बाद मध्य प्रदेश संविदा कर्मचारी आदेश के लिए राज्य सरकार के अध्यक्ष रामेश राठौर के नेतृत्व में उत्तर आदेश करावायी की।

गैरतलब है कि कुकुट विकास निगम में संविदा नीति लागू की जाने के लिए उद्योगपति ने कहा कि इसके बाद मध्य प्रदेश संविदा कर्मचारी आदेश के लिए राज्य सरकार के अध्यक्ष रामेश राठौर के नेतृत्व में उत्तर आदेश करावायी की।

गैरतलब है कि कुकुट विकास निगम में संविदा नीति लागू की जाने के लिए उद्योगपति ने कहा कि इसके बाद मध्य प्रदेश संविदा कर्मचारी आदेश के लिए राज्य सरकार के अध्यक्ष रामेश राठौर के नेतृत्व में उत्तर आदेश करावायी की।

गैरतलब है कि कुकुट विकास निगम में संविदा नीति लागू की जाने के लिए उद्योगपति ने कहा कि इसके बाद मध्य प्रदेश संविदा कर्मचारी आदेश के लिए राज्य सरकार के अध्यक्ष रामेश राठौर के नेतृत्व में उत्तर आदेश करावायी की।

गैरतलब है कि कुकुट विकास निगम में संविदा नीति लागू की जाने के लिए उद्योगपति ने कहा कि इसके बाद मध्य प्रदेश संविदा कर्मचारी आदेश के लिए राज्य सरकार के अध्यक्ष रामेश राठौर के नेतृत्व में उत्तर आदेश करावायी की।

गैरतलब है कि कुकुट विकास निगम में संविदा नीति लागू की जाने के लिए उद्योगपति ने कहा कि इसके बाद मध्य प्रदेश संविदा कर्मचारी आदेश के लिए राज्य सरकार के अध्यक्ष रामेश राठौर के नेतृत्व में उत्तर आदेश करावायी की।

गैरतलब है कि कुकुट विकास निगम में संविदा नीति लागू की जाने के लिए उद्योगपति ने कहा कि इसके बाद मध्य प्रदेश संविदा कर्मचारी आदेश के लिए राज्य सरकार के अध्यक्ष रामेश राठौर के नेतृत्व में उत्तर आदेश करावायी की।

गैरतलब है कि कुकुट विकास निगम में संविदा नीति लागू की जाने के लिए उद्योगपति ने कहा कि इसके बाद मध्य प्रदेश संविदा कर्मचारी आदेश के लिए राज्य सरकार के अध्यक्ष रामेश राठौर के नेतृत्व में उत्तर आदेश करावायी की।

गैरतलब है कि कुकुट विकास निगम में संविदा नीति लागू की जाने के लिए उद्योगपति ने कहा कि इसके बाद मध्य प्रदेश संविदा कर्मचारी आदेश के लिए राज्य सरकार के अध्यक्ष रामेश राठौर के नेतृत्व में उत्तर आदेश करावायी की।

गैरतलब है कि कुकुट विकास निगम में संविदा नीति लागू की जाने के लिए उद्योगपति ने कहा कि इसके बाद मध्य प्रदेश संविदा कर्मचारी आदेश के लिए राज्य सरकार के अध्यक्ष रामेश राठौर के नेतृत्व में उत्तर आदेश करावायी की।

गैरतलब है कि कुकुट विकास निगम में संविदा नीति लागू की जाने के लिए उद्योगपति ने कहा कि इसके बाद मध्य प्रदेश संविदा कर्मचारी आद